आकाशवाणी शिमला

15.05.2025 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

परीक्षा परिणाम

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा इस वर्ष मार्च में ली गई 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा परिणाम 79 दशमलव 8 प्रतिशत रहा और कुल 95 हजार 4 सौ 95 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में छात्राओं ने पहले तीन स्थानों पर बाजी मारी है। हेमराज बैरवा ने बताया कि कांगड़ा जिला के न्यूगल मॉडल पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल भवारना की छात्रा सायना ठाकुर ने 7 सौ में से 6 सौ 96 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इसी तरह बिलासपुर जिला के आर.के. सीनियर सैकेंडरी स्कूल घंडालवीं की रिद्धिमा शर्मा ने 7 सौ में से 6 सौ 95 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। मॉडर्न पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल स्वारघाट की मुदिता शर्मा और मिनरवा सीनियर सैकेंडरी स्कूल घुमारवीं की छात्रा प्रियंका शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि यह उल्लेखनीय परिणाम विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, निरंतरता और पढ़ाई के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं। आज शिमला में विशेष उच्चाधिकार क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि समिति पारदर्शी तरीके से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी मशीनरी और उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए स्थापित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रदेश भर में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर है। बैठक में समिति ने पांच फेको मशीनों की खरीद के लिए स्रोत और दरों को मंजूरी दे दी है।

रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर स्कूलों के विलय व पुनर्गठन पर भी विचार किया जा रहा है। शिमला में शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले अढाई वर्षों में लगभग 12 सौ स्कूल बंद किए गए हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि जीरो इनरोलमेंट वाले करीब 100 स्कूल डिनोटिफाई किए जाएंगे और नियमों के अनुसार इन स्कूलों का मर्जर या डाउन ग्रेडिंग किया जाएगा। इसके साथ ही, कई स्कूलों को को–एजुकेशन मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा।

100 के आसपास ऐसे स्कूल होंगे जहां पर आपकी जीरो एनरोलमेंट है और डिनोटिफाई होंगे लेकिन इसके अलावा जैसे हमने प्लस टू का एक मानक बनाया था उसमें उदाहरण के तौर पे विदीन 5 किलोमीटर्स का हमने प्लस टू का मापदंड रखा हैऔर एनरोलमेंट आपकी छठी से लेकर 12वीं तक अगर 25 है या 25 से कम है और विदिन 5 किलोमीटर्स आपका दूसरा प्लस टू उपलब्ध है तो आपका वह स्कूल मर्ज होगा और डाउन ग्रेड का भी हमने प्रस्ताव बनाया है वह दो प्रस्ताव है और अगर आपकी इनरोलमेंट आपकी में 10 से कम होती है प्लस वन प्लस टू में तो वह भी स्कूल जो आपका 5 किलोमीटर से ऊपर है तब तो वह स्कूल कंटिन्यू करेगा 5 किलोमीटर से कम है तो उसको मर्ज करेंगे। शिक्षा मंत्री, रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस महीने के अंत तक शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी जाएगी और नई ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है।

भेंट

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से भेंट की। उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेषकर अनुसूचित जाति विकास योजना एस.सी.डी.पी. के अंतर्गत बजट में कटौती के संबंध में चर्चा की। कुलदीप कुमार ने राज्य के लिए अनुसंधान व विकास प्रभाग के अंतर्गत बजट प्रावधान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने छावनी क्षेत्रों में या उनके समीप रहने वाली आबादी के मुद्दों को हल करने के लिए आयोग से हस्तक्षेप करने और इन्हें रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया। कुलदीप कुमार ने आयोग की गतिविधियों के बारे में भी अध्यक्ष को अवगत करवाया और कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान आयोग को सुरक्षा प्रदान करने का भी अनुरोध किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने उनके मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और राज्य को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

पंजीकरण अभियान

प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों के बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीकरण करने के लिए एक माह का विशेष अभियान आज से आरम्भ किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को इस अभियान को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मिशन मोड पर चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके। प्रवक्ता ने बताया कि यह अभियान इस वर्ष 15 जून तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की ओर से शिविर लगाकर किसानों का योजना के तहत पंजीकरण किया जाएगा।

———————————————